

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 148/2021

दायर दिनांक : 23-03-2021

उनवान

1. शंकर पिता छीतर जाति जाट निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरू पिता मांगू जाति जाट निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।
2. बंदी पिता लक्ष्मण जाति जाट निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।
3. रामेश्वर पिता मगना जाति जाट निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।
4. सोनाथ पिता बख्तावर जाति जाट निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।
5. मोती पिता रतना जाति जाट निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. श्री देवेन्द्र कुमार पोरवाल (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)

—: आदेश :-

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक : 07.07.2021

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण जरिये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारे सह खाते की ग्राम रलायता पटवार हल्का रलायता की सरहद में स्थित खाता संख्या 335 की आराजी संख्या 206,214,216,221,254,437,638,651,783 कुल किता 9 रकबा 4.5163 बीघा भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त आराजियात के पड़ौसी है जो आये दिन सीमाओ को लेकर एवं फसल काश्त करते समय, काटते समय विवाद करते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर विवाद नही रहे। उक्त आराजियात के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नही है। नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान करावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये पत्थरगढ़ी किये हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रार्थीगण के उक्त आराजियात संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से पत्थरगढ़ी किये जाने में कोई आपत्ति नही की गई।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2074-77 के अवलोकन से प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी के संयुक्त खातेदार है। पड़ौसियान का विवाद करने का शपथ पत्र संलग्न है। चूंकि प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमी